DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI , WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2024

Illegal construction on a 'scale previously unheard of': HC

Abhinav.Garg@timesgroup.com

New Delhi: Illegal construction is going on in Delhi on a "scale previously unheard of", often in the heart of the capital, Delhi High Court said on Tuesday, ordering a CBI probe into one such case.

"The property in question is a stone's throw away from the local police booth. From the documents on record, it is not clear as to how the property from a graveyard became a single-room godown and turned into a two-storey building and then a five-storey building. No permission or sanction from any statutory authority has been placed on record," a bench of acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet P S Arora noted, referring to the premises near ASI-protected Nizamuddin ki Baoli and Barakhamba tomb.

Deeply perturbed to find three additional floors were added while the building remained sealed by Municipal Corporation of Delhi (MCD), HC roped in CBI and said despite the multiplicity of authorities and an elaborate system of checks and balances, there is no fear of law and illegal construction has mushroomed.

The court observed that "encroachment is the worst form of civil wrong and it is like committing dacoity as the land-owning agency loses its land in the process and the public at large loses a valuable asset".

"This court is of the view that structural reforms are required in the working of respondents (authorities) to deal with illegal and unauthorised constructions of such giant magnitude. The issue of overlapping jurisdiction needs to be resolved by issuing clear and cogent practice directions," the bench said, directing the Delhi Development Authority (DDA) vice-chairman and the MCD commissioner to put structural reforms in place and devise new strategies to deal with the menace of encroachment as well as illegal and unauthorised construction.

'REFORM NEEDED': Delhi High Court said the property, a stone's throw away from local police booth, had turned from a graveyard to a single-room godown to a two-storey building and then a five-storey building

HC was troubled that even today, MCD relies on tapes and strings to seal a building and punctures the roofs partially in the name of demolition of a structure, which is why the sealing and demolition action does not have any deterrent effect. HC said status quo suits the executive as it is "satisfied and unwilling to reform the system". The court called for use of easily accessible technologies, including drones, satellite images and digital maps, to counter the problem of encroachments and illegal construction.

HC was hearing a public interest litigation by NGO Jamia Arabia Nizamia Welfare Education Society which claimed that "illegal and unauthorised construction" was being carried out at Ziyrat guest house near Baoli gate, Hazrat Nizamuddin dargah, close to the police booth. The MCD counsel stated that even the ground, first and second floors were illegal and informed the court that the property has now been fully razed to the ground.

Underlining that responsibility needs to be fixed and the role of the parties involved in the illegal construction of the guest house examined, HC directed the MCD commissioner and the DDA vice chairman to launch an inquiry and fix liability on errant officials.

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2024 | 3

अनधिकृत निर्माण की जांच सीबीआइ को स्थानांतरित की

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध व अनधिकृत निर्माण पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से कहा कि इस मुद्दे से निपटने के लिए संरचनात्मक सुधार करने चाहिए। अदालत ने कहा कि आज के समय में भी एमसीडी किसी इमारत को सील करने के लिए टेप और स्ट्रिंग (सुतली, धागे) का उपयोग करना जारी रख रही है, यही कारण है कि सीलिंग और ध्वस्तीकरण कार्रवाई का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं हो रहा है।

एमसीडी-डीडीए से पूछा प्रश्न

एमसीडी और डीडीए के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी अधिकारी पांच मंजिला इमारत जितने बड़े अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे?

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने ने संरक्षित निजामुद्दीन दरगाह और बावली के पास एक गेस्ट हाउस के अनधिकृत निर्माण के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई एक प्राथमिकी की जांच सीबीआइ को स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जांच व संतुलन की विस्तृत व्यवस्था के बावजूद दिल्ली के बीचो-बीच इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है। सुनवाई के दौरान एमसीडी ने कहा कि गेस्ट हाउस डीडीए की जमीन पर है और ऐसे में डीडीए को प्राथमिक एजेंसी होने के नाते संपत्ति की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए था। वहीं, डीडीए ने तर्क दिया कि क्षेत्र में बिल्डिंग उपनियमों को विनियमित करने और लागू करने के साथ ही अवैध अतिक्रमण हटाने को कदम उठाना एमसीडी की जिम्मेदारी थी। याचिकाकर्ता जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी ने अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध जनहित याचिका दायर कर कार्रवाई करने की मांग की है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 21 फरवरी 2024

लुटियंस ज़ोन से खूबसूरत बनेगा द्वारका

एलजी ने मंगलवार को द्वारका में दो प्रोजेक्ट दिल्ली की जनता को किए समर्पित

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

सब सिटी द्वारका की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहां 80 फाउंटेन लगाए जाएंगे। पहले चरण में चार चौराहों पर फाउंटेन और आर्ट वर्क लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में द्वारका खूबसूरती के मामले में दिल्ली की सबसे शानदार जगह होगी। एलजी वी के सक्सेना ने यह बात द्वारका में कही। वह यहां द्वारका के एक चौक पर हुए ब्यूटीफिकेशन और दो स्ट्रॉम वॉटर चैनल का उद्घाटन करने आए थे। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में करीब 200 फाउंटेन और 100 आर्ट वर्क लगाए गए हैं। यह आर्टवर्क और फाउंटेन राजस्थान और उड़ीसा के हस्त शिल्पकारों ने बनाए हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली की खूबसूरती बढ़ाने का काम दूसरे राज्यों के लोगों को रोजगार दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में द्वारका में कई प्रोजक्ट्स पूरे होंगे।

एलजी ने मंगलवार को द्वारका सेक्टर-1 के चौराहों पर चार फाउंटेन के साथ स्ट्रॉम वॉटर चैनल 2 और पांच के प्रोजेक्ट को भी जनता को समर्पित किया। इस मौके पर उनके साथ पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूडी के साथ डीडीए के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर एलजी ने कहा कि दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाने का काम कुछ समय पहले शुरू हुआ है और यह लगातार स्पीड पकड़ रहा है। मौजूदा समय में डीडीए दिल्ली में कई विकास कार्य कर रहा है। द्वारका में डिप्लोमेटिक एनक्लेव और राज्य भवन को जमीन अलॉट की गई है।

ड्रेनेज समस्या होगी दूर: दो ड्रेन द्वारका के ड्रेनेज समस्या का हल करेंगी। यह ड्रेन द्वारका सेक्टर-8, 9, 20, 23, 19, 24 और सेक्टर-3, 13, 14 और 16 को आपस में जोड़ते हुए नजफगढ़ ड्रेन में मिलकर यमुना में गिरेगी। स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन 2 की लंबाई 5.2 किलोमीटर और ड्रेन नंबर 5 की लंबाई 3.8 किलोमीटर है।

द्वारका की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहां 80 फाउंटेन लगाए जाएंगे

एलजी ने कहा, द्वारका खूबसूरती के मामले में सबसे शानदार जगह होगी।

जल्द पूरे होंगे और कुछ प्रोजेक्ट

एलजी ने बताया कि द्वारका में आने वाले कुछ समय में 200 एकड़ मे बन रहा भारत वंदना पार्क पूरा होगा। इसके अलावा मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द्वारका में शुरू होने वाले हैं। इनमें वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही गोल्फ कोर्स भी यहां शुरू होने वाला है।

सिग्नेचर व्यू की RWA ने फ्लैट खाली करने के लिए जल्द किराये की मांग की

DDA को लिखा पत्र, कहा- डर के साये में जी रहे लोग

■ विशेष संवाददाता, मुखर्जी नगर

रहने के लिए अनसेफ करार हो चुके मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के लोगों ने डीडीए को पत्र लिखकर मांग की है कि जो लोग अपने फ्लैट को खाली करना चाहते हैं, डीडीए उनके लिए जल्द रेंट जारी करे। ताकि वह सुरक्षित रह सकें।

■ **ज्यादातर लोग फ्लैट खाली करना चाहते हैं**

15 फरवरी को लिखे गए इस लेटर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की आरडब्ल्यूए ने डीडीए से अपील की है कि ज्यादातर लोग अब खौफ के साये में रहना नहीं चाहते। इसलिए उनके लिए बिल्डिंग को खाली करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। यह भी लिखा गया है कि आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट आए हुए 15 महीने का समय बीत चुका है। इस रिपोर्ट में यह साफ लिखा था कि बिल्डिंग रहने के लिए अनसेफ है और इसे तुरंत खाली करवाकर डिस्मेंटल किया जाना चाहिए। इसमें रहने वाले लोगों के लिए खतरा है।

EMI और रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते

आरडब्ल्यूए के अनुसार, सिग्नेचर व्यू मे रहने वाले 70 प्रतिशत से अधिक लोग बिल्डिंग को खाली करना चाहते है और अपने फ्लैट को रिकंस्ट्रक्शन के लिए हैंडओवर करना चाहते है। लेकिन डीडीए ने अभी तक रेंट देने की प्रक्रिया शुरू नही की है। इस वजह से यह लोग अपने फ्लैट खाली नही कर पा रहे है और खौफ के साये मे जी रहे है। लोग ईएमआई और रेंट एक साथ अफोर्ड नही कर सकते।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times NEW DELHI WEDNESDAY FEBRUARY 21, 2024

Walkways and food court at Dwarka water channels

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant governor VK Saxena on Tuesday inaugurated two rejuvenated and beautified stormwater channels in the Dwarka sub-city, the Delhi Development Authority (DDA) said in a statement.

The two channels had become open sewers and have been cleaned up, with green spaces and "riverfront facilities" such as a cycle track, nature trails, walkways, yoga pavilions, decks, and pergola bridges built along them, with further provision for an open-air food court, DDA added.

The two channels — one 5.2-km-long and the other 3.8-km-long — pass through Dwarka's sectors 8, 9, 20, 23, 19, 24, 3, 13, 14, and 16, before merging with the Najafgarh drain which drains into the Yamuna.

"I compliment DDA for completing the work in a time-bound manner. The land has been allotted for a diplomatic enclave and state bhawans in Dwarka, which will bring national and international recognition to the sub-city," said LG Saxena.

A DDA official associated with the project said the channels had become open sewers. "A lot of domestic wastewater was discharged into these channels over the past few years from adjoining neighbourhoods and other areas lacking sewerage facilities. The channels became open sewers and resulted in inhospitable situations in nearby areas," said the official, adding that DDA intercepted and treated the waste being discharged into the channels.

Walkway along a drain inaugurated on Tuesday. VIPIN KUMAR/HT

The project has cost DDA ₹300 crore.

The DDA statement said that the channels will work as "greenways" connecting Metro stations to residential neighbourhoods and upcoming projects such as a golf course, the Bharat Vandana Park, and sports complexes.

"The channels will also incorporate a solar arcade consisting of 44 solar flowers with the capacity to generate 203KWp and 30 solar trees each with 1KWp capacity that will be used for lighting up the area," the official said.

DDA has also installed street light poles and CCTV cameras along the cycle track and walkway. "There is also provision for daily necessities such as an open-air food court, open-air theatre, yoga pavilion, children's park, and public toilets," the official said.

LG Saxena also inaugurated four cascade-type horse fountains at the intersection of Dwarka's sectors 1 and 7 and sectors 2 and 6. "The fountains are 12 feet high and have been built with redeveloped green areas and barrier-free ramps," the DDA official said.

Illegal structures in Nizamuddin to face CBI probe

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi high court on Tuesday directed the Central Bureau of Investigation (CBI) to probe illegal construction at a sealed guest house, located within 100 metres of the centrally protected monument Nizamuddin ki Baoli, saying that the scale at which unauthorised construction is going on in the Capital despite multiplicity of civic authorities and an elaborate system of checks and balances is unheard of.

Taking note of the failure of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) and Delhi Development Authority (DDA) to act against encroachment and illegal construction, the court opined that there was a need for the civic authorities to undertake structural reforms to improve its functioning.

The bench led by acting chief justice Manmohan directed the authorities to devise new strategies to deal with the issue, saying that encroachment is akin to dacoity as the land-owning agency in the process loses its land and the public loses its assets. "It is apparent that the administrative responsibility needs to be fixed and the role of the parties need to be examined. MCD commissioner and DDA vice-chairman are directed to ensure that inquiries are set up and responsibility is fixed. Since FIR (first information report) has already been registered by local police, this court directs transfer of the FIR to CBI," the bench, also comprising justice Manmeet Pritam Singh Arora, said in the order.

The court observed that structural reforms are required in the working of the respondents to deal with the issue of unauthorised construction. "In today's time, MCD is continuing to use tapes to seal a building and is normally puncturing the roofs partially in the name of demolition. No wonder the sealing and demolition actions are having no effect," the court said.

The court was considering a plea filed by an NGO, Jamia Arabia Nizamia Welfare Education Society, seeking to halt and demolish the illegal construction that was being carried out in the guest house, contending that a large number of unauthorised guest houses are running without legal permission from Nizamuddin West residential colony.

"From the documents on record it is not clear as to how the property from a graveyard to a single room godown became a single storey and five storied building. No documents have been placed on record," the court noted.

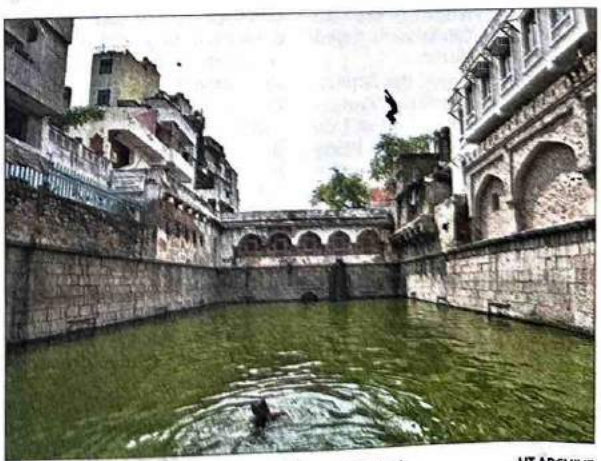

The baoli is a centrally protected monument. HT ARCHIVE

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2024

Drained Of Waste! Nature Trail, Food Court And More

Saxena Inaugurates Two Revamped Trunk Drains In Dwarka

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority's trunk drains in Dwarka, named No. 2 and No. 5, rejuvenated in a project to curb waterlogging and create green recreational space were inaugurated by lieutenant governor VK Saxena on Tuesday. Though some finishing work was required to be done when **TOI** visited the sites, officials claimed that all pending tasks would be completed by mid-March.

The Rs 300 crore project included tapping the around 15 drain outlets and treating their wastewater through three mega sewage treatment plants (STPs) before dumping it into the trunk drains connected to the Najafgarh drain. It also included creating recreational facilities along the 5.2km No. 2 drain including a nature trail, open air food court, open air theatre, three solar arcades and two ecological zones. Plans are also for the 3.8km drain No. 5, which passes through sectors 15, 13, 14, 17 and 16 of Dwarka, to have similar recreation facilities.

"We have constructed three STPs along these trunk drains," said an official on Tuesday. "Two STPs, one of 7 million litres a day (MLD) capacity and the other of 5MLD are on drain No. 2. Drain No. 5 has a 9.5MLD STP. Two STPs have been inaugurated, but work is in progress on the 5MLD one."

Saxena said treated water would be released into the drains in a month's time. "Tertiary plants are also being installed. The quality of water will be good and the biochemical oxygen demand will be less than 10. Since these two trunk drains will merge with Sahibi River, earlier called Najafgarh drain, the overall quality of water flowing into the Yamuna will improve," the LG said.

SMART TRANSFORMATION

Photos: Anindya Chattopadhyay

Storm water drain 2 and 5 pass through many sectors of Dwarka before merging with Najafgarh drain

Drain 2 5.2 km — Drain 5 3.8 km

THEY ARE ALSO CALLED TRUNK DRAINS

- Over the last few years, these drains discharged domestic waste water from adjoining colonies
- They became open sewers and resulted in inhospitable conditions for people in nearby areas
- To address these issues, DDA executed the project to rejuvenate these drains by sewerage interception and treatment

Three STPs constructed along these trunk drains

At drain 2: 7 MLD and 5 MLD (in progress)

At drain 5: 9.5 MLD

PROJECT ALSO INCLUDES
development of adjacent green buffer zones and open areas along these trunk drains

90% work completed and these will be opened by mid-April

RECREATIONAL FACILITIES

- 12km walking track, moorum path, natural trails, 9km cycling tracks, yoga path, secured entry gates, public toilets, children's play area, open air theatre, food court, pedestrians bridges, CCTV network

- Landscape lighting, food kiosks, arcade with 44 solar flowers generating 203KW per day electricity, etc
- Green corridors also connect to metro stations, residential areas and major public areas like Golf Course, Bharat Vandana Park, sports complex, etc

He added that the connection of the airport drain near Sector 8 Dwarka to drain No. 2 would be finished in two months and this would take care of the problem of waterlogging in and around the airport.

Among the recreational facilities developed on the sides of these drains are a 12km walking track, a 9km cycling track, yoga path, public toilets, children play area, open air theatre, food court, and a solar arcade consisting of 44 solar flowers capable of generating 203kW per day of electricity and 30 solar trees each with 1kW capacity. The power generated will be used for the illumination of the project area.

"On trunk drain No. 2, there are two recreational complexes, one at Sector 9 with 30 kiosks and another nearby with six food kiosks. On No. 5, there are three complexes at sectors 13, 3 and 16 with food kiosks," said the official.

Officials claimed that the rejuvenated channels would provide a green and clean environment for walks, jogging, cycling, even the daily commute to work. Riverfront amenities include viewing decks, pergola bridges and check dams. Work is under way on some of these facilities between the drain and Bharat Vandana Park.

On Tuesday, the LG also inaugurated four cascade-type horse fountains at the intersection of Sector 1/7 and Sector 2/6 in Dwarka. He added that there is a plan to install 80 such fountains in and around the sub-city.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- हिन्दुस्तान ----------DATED----------

दिल्ली के दिल में अवैध निर्माण जारी: हाईकोर्ट

अदालत से

- निजामुद्दीन की बावली के पास कब्जे की जांच सीबीआई को सौंपी
- कहा, ऐसे मामलों से निपटने के लिए संरचनात्मक सुधार करें

नई दिल्ली, एजेंसी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली के दिल में अवैध निर्माण कार्य जारी है, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों और तमाम नियम कानून के बावजूद ये सब हो रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने ये टिप्पणी मंगलवार को की। अदालत ने कहा कि उसे लगता है कि बिल्डरों के भीतर कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है। अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को आदेश दिया कि वे अतिक्रमण, अवैध और अनधिकृत निर्माण से निपटने के लिए संरचनात्मक सुधार का खाका पेश करे। अदालत ने संरक्षित निजामुद्दीन की बावली और बाराखंभा मकबरे के पास एक गेस्ट हाउस के अनधिकृत निर्माण के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज केस को सीबीआई को स्थानांतरित करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ एनजीओ जामिया अरबिया निज़ामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें दावा किया गया था कि बावली गेट के पास खसरा नंबर 556 में अवैध निर्माण किया जा रहा था।

टेप से सील हो रही बिल्डिंग : अदालत ने कहा कि आज के समय एमसीडी टेप और रस्सी से भवनों को सील कर रहा है। ध्वस्तीकरण के नाम पर वे छतों को आधा अधूरा तोड़ रहा है। यही कारण है कि सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। नतीजतन अवैध निर्माण का सिलसिला जारी है।

अधिकारी सुधार को तैयार नहीं : पीठ

अधिकारियों पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा, अधिकारी यथास्थिति से संतुष्ट हो जाते हैं। वे ड्रोन, उपग्रह छवियों और डिजिटल मानचित्रों जैसी आसानी से उपलब्ध तकनीक के उपयोग से व्यवस्था सुधारने को तैयार नहीं है। वे ऐसा करें तो बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण और अवैध निर्माण का पता चल सकेगा। अदालत ने कहा, उसे लगता है कि इतने बड़े आकार के अवैध- अनधिकृत निर्माणों से निपटने के लिए प्राधिकरणों के कामकाज में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार के मुद्दे को स्पष्ट और ठोस दिशा- निर्देश जारी करके हल करने की जरूरत है।

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2024 दैनिक जागरण

सांसद क्षेत्र की जरूरतों से कराएं अवगत : उपराज्यपाल

द्वारका में पुनर्विकसित स्टार्म वाटर चैनल और अन्य जगहों पर दो फव्वारों का एलजी ने किया उद्घाटन

- बोले, मैं कराऊंगा सभी कार्य, बस होनी चाहिए इच्छाशक्ति
- कहा, अब पूरी दुनिया में होने लगी है उपनगरी द्वारका की पहचान

द्वारका में पुनर्विकसित स्टार्म वाटर चैनल का उद्घाटन करते एलजी वीके सक्सेना • जागरण

जासं, पश्चिमी दिल्ली : द्वारका में पुनर्विकसित स्टार्म वाटर चैनल दो एवं पांच और दो विभिन्न स्थानों पर फव्वारों के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के सभी सांसद उन्हें अपने-अपने क्षेत्र की जरूरतों से अवगत कराएं, मैं उनका कार्य कराऊंगा। कोई भी कार्य आसान नहीं होता है, लेकिन इच्छाशक्ति हो तो कोई भी कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जी-20 के आयोजन के बाद जब वे द्वारका के दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने जगह-जगह जलभराव की समस्या देखी थी, तब इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था। अब न केवल द्वारका, बल्कि आसपास के इलाकों में भी जलभराव की समस्या नहीं होगी। ऐसा केवल इच्छाशक्ति से ही संभव हुआ। कार्यक्रम में पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी सहित कई लोग मौजूद रहे।

उपराज्यपाल ने कहा कि उपनगरी द्वारका की पहचान अब पूरी दुनिया में होने लगी है। हाल ही में विश्व की बड़ी प्रदर्शनी स्थलों के लिए यशोभूमि का निर्माण कार्य पूरा हुआ। राजधानी के दूसरे डिप्लोमेटिक एंक्लेव का निर्माण द्वारका में शुरू हो चुका है। कई राज्य यहां अपने भवन का निर्माण करा रहे हैं। मिनी इंडिया थीम पर भारत वंदना पार्क का निर्माण जोरशोर से हो रहा है। इस पार्क में देश के प्रत्येक राज्य की सांस्कृतिक धरोहर की रेप्लिका देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट ड्रेन का निर्माण कार्य चल रहा है। सभी कार्य तेजी से हो रहे हैं।

पुनर्विकसित स्टार्म वाटर चैनल दो एवं पांच पर एलजी ने कहा कि दोनों चैनलों को शोधित पानी से भरा जाएगा। जब इनमें शोधित पानी का बहाव होने लगेगा तब यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हो जाएगा। दोनों चैनलों के लिए दो एसटीपी बनाए गए हैं। इनमें जिस पानी का बहाव होगा, उसमें पानी की गुणवत्ता ऐसी होगी कि इनका इस्तेमाल पेड़-पौधे की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर चैनल के पानी का इस्तेमाल भवन निर्माण कार्य में भी किया जा सकेगा। एलजी ने द्वारका में दो अलग-अलग चौराहों पर निर्मित फव्वारों के उद्घाटन पर कहा कि इन फव्वारों का निर्माण राजस्थान के कुशल शिल्पकारों ने किया है। इससे पूर्व जो फव्वारे व कलाकृतियां बनाई गई हैं, उन्हें राजस्थान व ओडिशा के शिल्पकारों ने बनाया है।

गुजरात माडल पर दिल्ली में हो रहे विकास कार्य : बिधूड़ी

कार्यक्रम में मौजूद दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में जो कार्य प्रदेश सरकार को करने चाहिए वे कार्य उनके गैर जिम्मेदाराना तरीके के कारण एलजी को अपने हाथ में लेने पड़ रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि एसटीपी का निर्माण डीडीए को करना पड़ा, जबकि यह कार्य जलबोर्ड का है। एलजी को दिल्ली की फिक्र है तो वे अपने स्तर पर कार्य कराते हैं। जिस तरह से दिल्ली में विकास कार्य हो रहे हैं, कहा जा सकता है कि ये कार्य गुजरात माडल की तर्ज पर हो रहे हैं।

एलजी सदैव रहते हैं उपलब्ध : प्रवेश वर्मा

पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे एलजी मिले हैं, जो नागरिकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अधिकारी की बात करें तो वे शनिवार और रविवार को अपने घर से भी बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब एलजी खुद तो निकलते ही हैं, अधिकारियों को भी जमीनी स्थिति का पता करने के लिए सड़कों पर निकलने को कहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली देहात की जमीनी स्थिति का पता लगाने को गांव में रात्रि विश्राम करने को कहा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- 21 फरवरी • 2024 | राष्ट्रीय सहारा

हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने राजधानी में हो रहे अवैध निर्माण पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण को कोई देखने वाला नहीं है। कोर्ट ने इसे देखते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से कहा कि वह इस तरह के मुद्दे से निपटने के लिए संरचनात्मक सुधार करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि आज के समय में एमसीडी किसी इमारत को सील करने के लिए टेप और स्ट्रिंग का उपयोग कर रही है, लेकिन सीलिंग एवं तोड़ने की कार्रवाई का कोई ठोस प्रभाव नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट ने मामले में एक अवैध निर्माण की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी।

पीठ ने कहा कि कार्यपालिका यथास्थिति से संतुष्ट लगती है और डिजिटल मानचित्र जैसी आसान तकनीकों के जरिए सिस्टम में सुधार करने को तैयार नहीं है, जिससे बड़े पैमाने पर किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माण का आसानी से पता लगाया जा सकता है। उसने उक्त टिप्पणी करते हुए केंद्रीय संरक्षित निजामुद्दीन दरगाह और बावली के पास एक गेस्ट हाउस के अनधिकृत निर्माण को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक प्राथमिकी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करते हुए की।

- हाईकोर्ट ने ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए एमसीडी व डीडीए को संरचनात्मक सुधार करने का दिया निर्देश
- संरक्षित बाराखंभा मकबरा और निजामुद्दीन बावली के 50 मीटर के दायरे में बन रहा था गेस्ट हाउस

पीठ ने कहा कि नियंत्रण और संतुलन की विस्तृत व्यवस्था के बावजूद दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है, जो अभूतपूर्व और अनसुना है। उसने कहा कि इसको लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और गेस्ट हाउस के अवैध निर्माण में पक्षों की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। पीठ ने इसके साथ ही एमसीडी आयुक्त और डीडीए के उपाध्यक्ष से कहा कि अवैध निर्माण को लेकर जांच कर इसके जिम्मेवार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उसने यह भी कहा कि पुलिस ने पहले से ही एक प्राथमिकी दर्ज कर रखी है, इसलिए यह अदालत इसकी जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश देती है।

कोर्ट ने यह निर्देश जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। उसमें डीडीए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और अन्य प्राधिकरणों के अनाधिकृत निर्माण को रोकने में विफलता के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। विचाराधीन गेस्ट हाउस का निर्माण केंद्रीय संरक्षित स्मारक बाराखंभा मकबरा और निजामुद्दीन बावली के 50 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र में किया जा रहा था। याचिका में गेस्ट हाउस को तोड़ने की भी मांग की गई है।

द्वारका के सौंदर्यीकरण की योजना का राज्यपाल ने किया शुभारंभ

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को द्वारका में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सौंदर्यीकरण योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बरसाती पानी की निकासी के लिए चैनल विकसित किए जाएंगे। आवासीय क्षेत्र के मेट्रो स्टेशनों को गोल्फ कोर्स, भारत वंदना पार्क एवं खेल परिसरों से जोड़ने के लिए ग्रीनवे चैनल विकसित होंगे। इससे साइकिल चलाने की सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। इस मौके पर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी समेत अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद थे।

उप-राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि इज ऑफ लिविंग और मौजूदा संरचना को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) लगातार काम कर रहा है। संबोधन से पहले उन्होंने द्वारका में आईलैंड फव्वारे, स्ट्राम वाटर चैनल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि डीडीए की योजना है कि इस क्षेत्र को विश्वस्तरीय सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया जाए। सौंदर्यीकरण का कार्य अभी शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में यह रफ्तार पकड़ेगा। उप-राज्यपाल ने कहा कि द्वारका में डिप्लोमैटिक एन्क्लेव और राज्य भवनों के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। इससे उप-नगर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

द्वारका उप-नगर को सुंदर बनाने के लिए स्ट्राम वाटर चैनल 2 और 5 का पुनोंद्धार किया गया है। डीडीए ने हरित बफर जोन और खुले स्थानों से सटे क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ सीवरेज अवरोधन और शोधन द्वारा चैनलों को फिर से जीवंत करने के लिए परियोजना की शुरुआत की है। 9 किलोमीटर लंबाई वाले इस चैनल से मेट्रो स्टेशनों के आसपास के आवासीय क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए 44 सोलर फ्लावर से युक्त एक सोलर आर्केड भी शामिल है। इसकी क्षमता 203 के डब्ल्यूपी उत्पन्न करने की है और इसमें 30 सोलर ट्री हैं। उप-राज्यपाल ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए साइकिल ट्रैक और पैदल मार्ग पर स्ट्रीट लाइट के खंभों की व्यवस्था के साथ-साथ सीसीटीवी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसमें साइकिल ट्रैक, नेचुरल ट्रेल्स और वॉकवे की सुविधा है। ओपन एयर फूड कोर्ट, ओपन एयर थिएटर, योग मंडप, चिल्ड्रन पार्क और आसानी से सुलभ सार्वजनिक शौचालय जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की सुविधा का प्रावधान है। इसके अलावा, व्यूइंग डेक, पेर्गोला ब्रिज, चेक डैम सहित रिवरफ्रंट एक्टिविटीज की सुविधा भी है। प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ की लागत आई है। सुंदरता बढ़ाने के लिए सेक्टर 1/7 और सेक्टर 2/6 द्वारका के चौराहे पर 12 फीट के 4 कैस्केड टाइप हॉर्स फाउंटेन बनाए गए हैं।

- वाटर चैनल से यमुना की सफाई में मिलेगी मदद
- बरसाती पानी की निकासी के लिए विकसित किए जाएंगे चैनल

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NAME OF NEWSPAPERS | WEDNESDAY | FEBRUARY 21, 2024 DATED----------

LG inaugurates island fountains, storm water channels in Dwarka

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Tuesday inaugurated island fountains and storm water channels (SWC) 2 and 5 in Dwarka. The rejuvenated channels will provide a green and clean, refreshing environment for the public to go out for walks, jogging, cycling and daily commute to and from work.

This is as per the commitment of the Delhi Development Authority (DDA) to develop world class infrastructure along with green space and beautify the Dwarka sub city. West Delhi MP Parvesh Sahib Singh and South Delhi MP Ramesh Bidhuri, and other senior officials of the DDA were also present. The project has been completed by DDA at the cost of Rs 300 crore. The SWC 2 has capacity of 7 MLD and SWC 5 has 9.5 MLD capacity to treat sewage.The rejuvenation of storm water channels 2 and 5 to address the issue of drainage system, provide green space, add to the public amenities and beautify the Dwarka sub-city. SWC2 and SWC5 Channels pass through many sectors (8, 9, 20, 23, 19, 24 and Sectors 3, 13, 14, 16) of Dwarka before merging with Najafgarh drain which further falls into River Yamuna. SWC2 has length of 5.2 Km and SWC5 has a length of 3.8 Km. Over the past few years, these channels have been subjected to discharge of domestic waste waters from adjoining colonies and other areas lacking sewerage facilities. The channels became open sewers and resulted in inhospitable situations in the nearby areas.

To address these pollution issues and boost the overall environmental wellbeing, DDA executed this project to rejuvenate the channels by sewerage interception and treatment along with area development of adjacent green buffer zones and open areas. The channels to act as greenways connecting metro stations to the residential areas and major public areas like Golf Course, Bharat Vandana Park, sports complex etc. along the entire length of 9 km and also incorporate a solar arcade consisting of 44 nos. of solar flower with the capacity to generate 203KWp and 30 nos. of solar tree each having capacity of 1KWp for harnessing solar energy to be used for the lighting in the project area. All the solar power facility is on grid.

Speaking at the event, Lt Governor said that beautification work of Delhi has just begun and it will continue at a faster pace in the days to come, adding that lots of developmental work have been undertaken in the national capital in the recent past."I compliment DDA for their hard work and completing the work in a time bound manner," he said. He further added land has been allotted for Diplomatic Enclave and state bhawans in Dwarka, which will give national and international recognition to the sub-city.

The street light poles all along the cycle track and walk way is also provided along with the facility of CCTV for the security and surveillance of the commuters. There is inclusion of amenities such as a cycle track, mooram path, natural trails, and walkways, provision of daily necessities like an open air food court, open air theatre, yoga pavilion, children park, and easily accessible public toilets. Furthermore, there are riverfront activities including viewing decks, pergola bridges, check dams.

The 4 cascade-type horse fountains of 12 feet each, constructed at the intersection of sector 1/7 and sector 2/6 Dwarka, to further add to the aesthetic beauty of the place. The fountains have redeveloped green areas and barrier free ramps.

The DDA has been working on mission mode under the consistent guidance of Delhi LG towards the development of Dwarka sub-city and has recently accomplished many projects in this location, constructed affordable to premium houses, built a state-of-the-art DDA Sports Complex at Sector 17 for health and fitness enthusiasts, foot-over-bridges for pedestrian safety, utsavpandal to provide an economic festivity option to the residents of Delhi.

"Further developmental projects in Dwarka includes 200 acre Bharat Vandana Park that would add to the green cover of the city, Centres of Excellence are being developed in multiple sports like wrestling, weight lifting, boxing, etc. and a huge public golf course to further the public health and wellness. All these projects will be completed this year. The work on the construction of UER-II is fast nearing completion, given the rapid pace of execution, the allocations for 2023-24 have been enhanced from Rs. 920 crore to Rs. 1590 crore," the authority said in a statement.

THE HINDU

'Pay rent, help us move out,' apartment residents tell DDA

Residents of "structurally unsafe" Signature View Apartments (SVA) have written to the Delhi Development Authority (DDA), asking it to provide rent to those who are ready to vacate their flats as per the mutually agreed terms. The agency had offered to pay monthly rent to the residents till the redevelopment is concluded as part of a rehabilitation package, the residents say. However, in a letter to the urban body on February 15, SVA's residents' welfare association said that despite a majority of the residents expressing their willingness to vacate their flats, the DDA had not acknowledged their proposal.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI

21/02/24

द्वारका सबसिटी में लोग ले सकेंगे एक अलग ही लाइफ का आनंद : उपराज्यपाल

एलजी ने की स्टॉर्म वॉटर चैनलों की शुरुआत

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): इज ऑफ लिविंग और सशक्त आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को द्वारका में आईलैंड फव्वारे और स्टॉर्म वॉटर चैनल 2 और 5 का उद्घाटन किया। यह दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के ग्रीन एरिया के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने और द्वारका सबसिटी को सुंदर बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस अवसर पर सांसद प्रवेश साहिब सिंह व रमेश बिधूड़ी सहित डीडीए अधिकारी व अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान एलजी ने कहा कि दिल्ली के सौंदर्यीकरण का काम अभी शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में यह तेज गति से जारी रहेगा। हालही के दिनों में डीडीए द्वारा इसके बाद उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में राजधानी में बहुत सारे विकास कार्य

किए गए है। द्वारका में डिप्लोमैटिक एन्क्लेव और राज्य भवनों के लिए भूमि आवंटित की गई है, जिससे सबसिटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। यहां लोग एक अलग तरह की लाइफ का आनंद ले सकेंगे। यहां के ड्रेन में ट्रीटमेंट किया हुआ हाई क्वालिटी का पानी डाला जाएगा। वह ऐसा पानी होगा जो कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जा सकता है। यशोभूमि से द्वारका की इंटरनेशनल पहचान बनी है। यहां अलग-अलग राज्यों के भवन भी बन रहे हैं। भारत वंदना पार्क भी द्वारका की अलग पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन पैचेज को डेवलप किया गया है। ड्रेन के साथ ग्रीनरी बनाई गई है। रेस्टोरेंट बनाए गए हैं जो जल्दी चालू हो जाएंगे। लोग यहां पर आकर एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति लेंगे। उन्होंने कहा कि नए तरीके से ड्रेन की शुरुआत, एचटीसी की शुरुआत, साइकिल ट्रैक व पानी कार ट्रैक सब तैयार किए जा रहे हैं। जिससे द्वारका के लोगों को एक अलग अनुभूति तो होगी ही वाटर लॉगिंग की समस्या से भी जूझना नहीं पड़ेगा।

सांसद प्रवेश वर्मा ने बताया कि इन कार्यों से आसपास की जनता को अनगिनत फायदे होने वाले हैं। नजफगढ़ ड्रेन के गंदे पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पानी स्वच्छ कर वाटर चैनलों को सुंदर बनाया जाएगा, साथ ही इससे द्वारका में पानी भरने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। यहां बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले, ग्रीन पार्क, रेस्टोरेंट, योगा सेंटर, साइकिल ट्रैक, 30 सोलर ट्री, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा इत्यादि अनेकों सुविधाएं हैं, आसपास के हजारों लोग यहां टहलने आया करेंगे जिससे वे सभी स्वस्थ रहेंगे। वहीं सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि एलजी के पास जो भी काम लेकर जाते हैं, वह पूरा होता ही है।

केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों के पास अवैध निर्माण, हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में अभूतपूर्व पैमाने पर अवैध और अनधिकृत निर्माण हो रहा है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को इस समस्या से निपटने के लिए संरचनात्मक सुधार करने चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि आज के समय में, एमसीडी किसी इमारत को सील करने के लिए टेप और स्टिंग का उपयोग करना जारी रख रही है, यही कारण है कि सीलिंग और विध्वंस कार्रवाई का कोई निवारक प्रभाव नहीं हो रहा है। खंडपीठ ने कहा कि कार्यपालिका यथास्थिति से संतुष्ट लगती है और डिजिटल मानचित्र जैसी आसान तकनीकों के जरिए सिस्टम में सुधार करने को तैयार नहीं है, जिससे बड़े पैमाने पर किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माण का आसानी से पता लगाया जा सके। खंडपीठ ने केंद्रीय संरक्षित निजामुद्दीन दरगाह और बावली के पास एक गेस्ट हाउस के अनधिकृत निर्माण के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करते हुए यह आदेश पारित किया। खंडपीठ ने इस दौरान कहा कि नियंत्रण और संतुलन की विस्तृत व्यवस्था के बावजूद, दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर अवैध

दिल्ली उच्च न्यायालय
DELHI HIGH COURT

- निजामुद्दीन दरगाह और बावली के पास हुआ था अवैध निर्माण
- हाईकोर्ट ने डीडीए, एमसीडी की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी

निर्माण हो रहा है जो अभूतपूर्व और अनसुना है और वह भी दिल्ली के बीचोबीच। प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है और गेस्ट हाउस के अवैध निर्माण में पार्टियों की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। खंडपीठ ने एमसीडी आयुक्त और डीडीए के उपाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जांच की जाए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। खंडपीठ ने कहा कि चूंकि पुलिस द्वारा पहले से ही एक एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए यह अदालत एफआईआर की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश देती है, जिसे तथ्यों की जांच करने और यदि कोई आपराधिक अपराध बनता है तो मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने का निर्देश दिया जाता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | WEDNESDAY, 21 FEBRUARY, 2024 RS----------DATED----------

L-G inaugurates fountains at Dwarka

DDA convenes rejuvenation project for storm water channels

L-G VK Saxena during the inauguration, in New Delhi on Tuesday.

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Lieutenant Governor (L-G) of Delhi, V K Saxena inaugurated island fountains and storm water channels (SWC) in Dwarka on Tuesday, in the presence of Member of Parliaments, Parvesh Sahib Singh and Ramesh Bidhuri.

Saxena inaugurated 4 cascade-type horse fountains of 12 feet each at the interceptions of Sectors 1 and 7, and Sectors 2 and 6.

The SWC rejuvenation is expected to address drainage problems in the city, provide green space and aid in public amenities. With lack of proper sewage system, the channels have been discharging domestic waste from nearby colonies and areas that lack a sewage.

As a result, the SWCs have become open sewers. The Delhi Development Authority (DDA) undertook the rejuvenation project to tackle pollution, with an estimate cost of Rs 300 crores.

The channels 2 and 5 pass through Dwarka Sectors 8, 9, 20, 23, 19, 24, 3, 13, 14, and 16 before merging with the Najafgarh drain, failing into the Yamuna river.

SWC 2 is 5.2 kms long, while SWC 5 has a length of 3.8 kms. They have been rejuvenated by sewerage interception and treatment, while simultaneously working on developing the surrounding areas

"The channels are to act as greenways connecting metro stations to the residential areas and major public areas like Golf Course, Bharat Vandana Park, sports complex etc. along the entire length of 9 km and also incorporate a solar arcade consisting of 44 of solar flower with the capacity to generate 203KWp and 30 nos. of solar tree each having capacity of 1KWp for harnessing solar energy to be used for the lighting in the project area," said DDA.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

द्वारका में छाएगी हरियाली, बढ़ेंगी सार्वजनिक सुविधाएं

उपराज्यपाल ने आईलैंड फव्वारे और स्ट्रॉम वाटर चैनल-दो और पांच का किया उद्घाटन

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। ईज ऑफ लिविंग और सशक्त आधारिक संरचना को बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को द्वारका में आईलैंड फव्वारे और स्ट्राम वाटर चैनल-दो और पांच का उद्घाटन किया।

यह योजना डीडीए की हरित क्षेत्र के साथ-साथ विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने और द्वारका उप नगर को सुंदर बनाने की कड़ी का हिस्सा है। इस दौरान सांसद प्रवेश वर्मा व रमेश बिधूड़ी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इस मौके पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के सौंदर्यीकरण का काम अभी शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में यह तेज गति से जारी रहेगा। द्वारका में डिप्लोमेटिक एन्क्लेव और राज्य भवनों के लिए भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से उपनगर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

इस कड़ी में यहां पर ड्रेनेज सिस्टम की समस्या का समाधान करने, हरित स्थान प्रदान करने, सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ाने और द्वारका उप नगर को सुंदर बनाने के लिए स्ट्राम वाटर चैनल-दो और पांच का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया।

एसडब्ल्यूसी दो और एसडब्ल्यूसी पांच चैनल नजफगढ़ नाले में विलय से पहले द्वारका के कई सेक्टरों से होकर गुजरते हैं और यह यमुना में मिलते हैं। उन्होंने कहा कि डीडीए ने हरित बफर जोन और खुले स्थानों से सटे क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ सीवरेज अवरोधन और शोधन के माध्यम से चैनलों को फिर से जीवंत करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की है। ये चैनल नौ किलोमीटर की पूरी लंबाई के साथ मेट्रो स्टेशनों को आवासीय क्षेत्रों और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे गोल्फ कोर्स, भारत वंदना पार्क, खेल परिसर से जोड़ने वाले ग्रीनवे के रूप में कार्य करेंगे।

उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए स्ट्रॉम वाटर चैनल के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया। अमर उजाला

फव्वारों के माध्यम से हरे-भरे क्षेत्रों और अवरोध मुक्त रैंप का किया पुनर्विकास

उपराज्यपाल ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए साइकिल ट्रैक और पैदल मार्ग पर स्ट्रीट लाइट के खंभों की व्यवस्था के साथ-साथ सीसीटीवी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसमें साइकिल ट्रैक, नेचुरल ट्रेल्स और वॉकवे की सुविधा भी शामिल हैं। ओपन एयर फूड कोर्ट, ओपन एयर थियेटर, योग मंडप, चिल्ड्रन पार्क और आसानी से सुलभ सार्वजनिक शौचालय जैसी दैनिक आवश्यकताओं का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ब्यूइंग डेक, पेर्गोला ब्रिज, चेक डैम सहित रिवरफ्रंट एक्टिविटीज भी हैं। इस योजना पर 300 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इलाके में सुंदरता बढ़ाने के लिए द्वारका के चौराहों पर 12 फीट के चार कैस्केड टाइप होर्स फाउंटेन बनाए गए हैं। फव्वारों के माध्यम से हरे-भरे क्षेत्रों और अवरोध मुक्त रैंप का पुनर्विकास किया है।

संरक्षित निजामुद्दीन दरगाह और गेस्ट हाउस के अनधिकृत निर्माण की जांच सीबीआई को

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कहा, राजधानी में बड़े पैमाने पर अवैध और अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं। अदालत ने इससे निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को संरचनात्मक सुधार करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने संरक्षित निज़ामुद्दीन दरगाह और बावली के पास एक गेस्ट हाउस के अनधिकृत निर्माण के मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करते हुए यह आदेश पारित किया।

इतना ही नहीं अदालत ने एमसीडी आयुक्त और डीडीए के उपाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जांच स्थापित की जाए और इसके अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का भी निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि आज के समय में एमसीडी किसी इमारत को सील करने के लिए टेप और स्ट्रिंग का उपयोग करना जारी रख रही है। यही कारण है कि सीलिंग और विध्वंस कार्रवाई का कोई निवारक प्रभाव नहीं हो रहा है।

समिति का गठन

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार,निगम के स्वामित्व वाले अस्पतालों में बुनियादी ढांचे के साथ मानव बल में सुधार एवं अन्य अनुकूल सुधार को लेकर सिफारिशें व सुझाव देने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। पीठ ने आईएलबीएस के चांसलर डा. एसके सरीन को समिति का अध्यक्ष बनाया है। अन्य सदस्य एम्स के एंडोक्रोनोलॉजी एवं मेटाबॉलिज्म विभाग केमुखिया डा. निखिल टंडन, डा. डीके शर्मा, एलएनजेपी के निदेशक डा. सुरेश कुमार, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज़ के प्रिंसिपल डा. पीयूष गुप्ता, आईएलबीएस के डा. दीपक के. टेम्पे शामिल हैं। ब्यूरो